







# संपादकीय

## संविधान पर चर्चा के मायने

ੴ

**लो** कसभा में सर्विधान पर दो दिवसीय चर्चा का दृश्य पूरे देश ने देखा। लोकसभा में सर्विधान पर बहस के बाद माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी का उत्तर सुनकर समझा में आ गया कि उन्होंने संघ की साखा में सर्विधान के बारे में जो कुछ पढ़ा-लिया उससे ज्यादा वे सर्विधान के बारे में जानते नहीं हैं। सर्विधान पर बहस के दौरान उठाये गए एक भी सवाल का उत्तर देने के बजाय वे अपने सिर पर सवार जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी के भूत को बिदारते नजर आये। वे नहीं बता पाए कि उनके युग में सर्विधान कैसे मजबूत हो रहा है? वे प्रधानमंत्री के स्तर का भाषण देने में हमेसा की तरह विफल हुए, उन्होंने सर्विधान पर भाषण देते समय सर्विधान पर अपने गहन अध्ययन का प्रदर्शन करने के बजाय सिफारिशों को सब उद्घाटित किया जो संघ की शाखाओं में स्थाय सेवकों को पिछले 100 साल से दीक्षित किया जा रहा है। मोदी जी संघ के पचारक हैं ये हकीकत है लेकिन वे देश के प्रधानमंत्री हैं इसलिए उन्हें शाखाओं के ज्ञान से ज्यादा सिखने की जरूरत है। उन्हें देश को बताना चाहिए था कि पिछले दस साल में उनकी सरकार में सर्विधान की रक्षा के लिए क्या कदम उठाये? सर्विधान संशोधनों को लेकर माननीय मोदी जी ने पिछली सरकारों के कामकाज को सर्विधान के साथ खिलवाड़ बताया, लेकिन जोर देकर कहा कि उनकी सरकार ने सर्विधान के साथ जो भी किया तो डंके की चोट किया। यानि वे परोक्ष रूप से कह रहे हैं कि -वे करें तो केरबटर ढाला, हम करें तो रास लीला। सर्विधान के साथ किस पार्टी और सरकार ने खिलवाड़? किया ये पूरा देश जानता है। कांग्रेस ने आपातकाल लगाया थे सभी को पता है। मोदी जी कहते हैं कि आपातकाल का कलंक कांग्रेस के माथे से कभी मिट नहीं सकता, लेकिन वे भूल जाते हैं कि इसी देश की जनता ने, विपक्ष की खिचड़ी जनता सरकार के गिरने के बाद मशीन और मशीनरी के बिना हुए आम चुनाव में कांग्रेस को विजय श्री देकर इस कलंक को मिटाया था। मेरा दृढ़ विश्वास है कि मोदी जी जब तक प्रधानमंत्री रहेंगे तब तक उनके सिर से जवाहर लाल नेहरू का, इंदिरा गांधी का, राहुल गांधी का यहां तक की राहुल गांधी का भूत उत्तरने वाला नहीं है और जब तक ये भूत उनके सर पर सवार रहेंगे वे न चैन से काम कर पाएंगे और न सर्विधान के विधान को समझ पाएंगे। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी देश को आश्वस्त नहीं कर पाए कि उनके लिए सर्विधान बड़ा है या मनुष्यता? वे ये स्पष्ट नहीं कर पाए कि उन्हें धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद शब्द से तकलीफ है या नहीं? वे ये भी नहीं बता पाए की सर्विधान को लेकर सावधारक जो सोचते थे, क्या वे उससे सहमत हैं या नहीं? मौजूदा सरकार ने पिछले एक दशक में सर्विधान की सेवा किस तरह से की है, देश और दुनिया जानती है। ऐसे में सोचना जरूरी है कि संसद में सर्विधान पर इस तरह की चर्चा की सार्थकता क्या है। क्यों कि पीएम को देश के सर्विधान की गरिमा, व्यापकता, प्रावधानों व आयामों का ज्ञान तो होना ही चाहिये।

# राज्यसभा के सभापति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का मुद्दा

୪

यह निष्पक्षता करने के लिए महत्वपूर्ण है कि संसदीय कायदावाही निष्पक्ष और निष्पक्ष तरीके से संचालित हो। हाल ही में, विषय ने राज्यसभा के सभापति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव उठाया, जिसमें उन पर पक्षपात करने का आरोप लगाया गया। यह स्थिति लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं की अखंडता के लिए प्रमुख नेतृत्व भूमिकाओं में निष्पक्षता बनाए रखने के महत्व को उजागर करती है।

# ऊर्जा संरक्षण से होगी बिजली की जरूरतें पूरी नजारिया

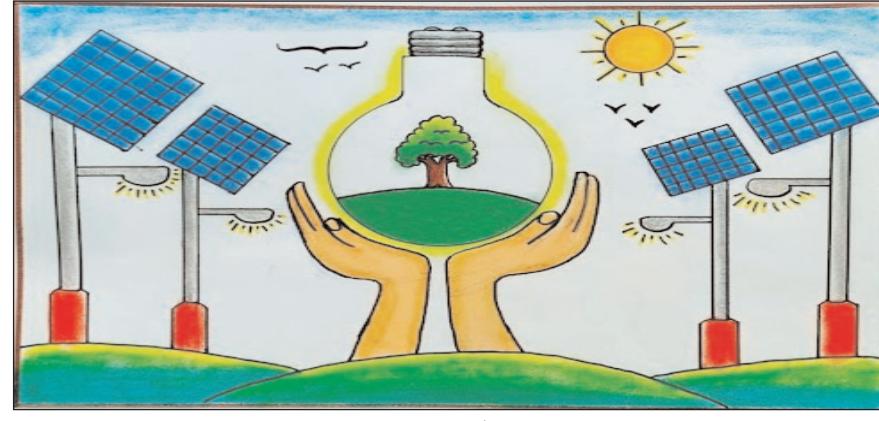
नजारिया

भारत में सौर ऊर्जा लगभग बारह महिने उपलब्ध है। सौर ऊर्जा को और अधिक उन्नत करने के लिए हमें अपने संसाधनों का उपयोग करना चाहिए। ऊर्जा के मामले में अधिक समय तक दूसरों पर निर्भर नहीं रहा जा सकता है। ऊर्जा के क्षेत्र में हमें अपनी तकनीक और संसाधनों का उपयोग कर आत्मनिर्भरता हासिल करनी ही होगा। यह दुख का विषय है कि बहुत लम्बे समय तक हमने सौर ऊर्जा के उत्पादन व उपयोग पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। हमारे देश की परिस्थितियां विषम होने के कारण हमें सभी उपलब्ध ऊर्जा विकल्पों पर विचार करना होगा। इसके साथ ही ऊर्जा संरक्षण के व्यावहारिक कदमों को अपनाना होगा ताकि बड़े पैमाने पर बिजली की बचत हो सके। हमारे देश में ऊर्जा की मांग तीव्रगति से बढ़ रही है। लेकिन उत्पादन में खपत की तुलना में बढ़ोतारी नहीं हो पा रही है। देश में चल रही पुरानी बिजली परियोजनाएं कभी पूरा उत्पादन नहीं कर पाई हैं। नई स्थापित

होने वाली परियोजनाओं के लिए स्थितियां अनुकूल नहीं होती हैं। देश में बिजली के इस संकट को अगर अभी समय रहते दूर नहीं किया गया तो आने वाले समय में गंभीर संकट का सामना करना होगा। दुर्भाग्यवश हमारे देश में खनिज, पेट्रोलियम, गैस, उत्तम गुणवत्ता के कोयला जैसे प्राकृतिक संसाधन बहुत सीमित गात्रा में ही उपलब्ध हैं। ऊर्जा की बचत किये बिना हम विकसित राष्ट्र का सपना नहीं देख सकते हैं। आज जिस तेजी के साथ हम प्राकृतिक और पराम्परिक ऊर्जा के स्रोतों का उपयोग कर रहे हैं। उस रपतार से 40 साल बाद हो सकता है हमारे पास तेल और पानी के बड़े भांडार खत्म हो जाए। उस स्थिति में हमें ऊर्जा के गैर-पारंपरिक स्रोतों यानि सौर ऊर्जा, परवन ऊर्जा जैसे साधनों पर निर्भए होना पड़ेगा। लेकिन ऊर्जा के गैर-पारंपरिक स्रोतों को इस्तेमाल करना थोड़ा मुश्किल है और इस क्षेत्र में कार्य अभी प्रगति पर है।

रमेश सर्गफ धमोरा

ह मार जावन म प्रातादन क बाब्हन काया व  
संचालन के लिए ऊर्जा अलंतं महत्वपूर्ण  
साधन है। दुनिया की अर्थव्यवस्था में वृद्धि के साथ-साथ  
प्रतिवर्ष ऊर्जा की मांग भी बढ़ती जा रही है। हम प्रतिदिन  
विभिन्न रूपों में ऊर्जा का उपयोग करते हैं। अतः भविष्य में  
ऊर्जा की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए इसका संरक्षण  
आवश्यक है। ऊर्जा संरक्षण से तात्पर्य विभिन्न उपयोगों के  
माध्यम से ऊर्जा का संरक्षण करना है। ऊर्जा संरक्षण के  
अंतर्गत विभिन्न कार्यों के माध्यम से ऊर्जा का उपयोग इस  
प्रकार किया जाता है। जिससे वर्तमान की आवश्यता कई<sup>पूर्ति</sup> के साथ भविष्य की जरूरतें भी पूरी हो सकें। ऊर्जा  
संरक्षण से तात्पर्य ऊर्जा का विवेकपूर्ण उपयोग है। इसके  
अर्थ है ऊर्जा का अनावश्यक उपयोग ना करना एवं कम से  
कम ऊर्जा का उपयोग करते हुए कार्य को करना। भारत एक  
ऐसा देश है जहां पूरे साल सारे ऊर्जा और पवन ऊर्जा का  
इस्तेमाल किया जा सकता है। भारत में साल भर में लगभग  
310 दिनों तक तेज धूप खिली रहती है। भारत भाग्यशाली  
देश है जिसके पास सारे ऊर्जा के लिए खिली धूप कई<sup>उपलब्धता</sup>, पर्यास मात्रा में भूमि की उपलब्धता, परमाणु  
ऊर्जा के लिए थोरियम का अथाह भंडार तथा पवन ऊर्जा वे  
लिए लंबा समुद्री किनारा नैसर्गिक संसाधन के तौर पर  
उपलब्ध है। जरूरत है तो बस उचित प्रैद्योगिकी का विकास  
तथा संसाधनों का दोहन करने की।



मेगावाट अथवा 43 प्रतिशत शामिल। देश में कोयले से 205,235 मेगावाट अथवा 49.3 प्रतिशत, लिमाइट से 6620 मेगावाट, हाईड्रोपावर (पनबिजली) से 46,850 मेगावाट यानि कुल क्षमता का 11.3 प्रतिशत, प्राकृतिक गैस से 24,824 मेगावाट यानि क्षमता का महज 6 प्रतिशत और परमाणु ऊर्जा से 6780 मेगावाट, सौर ऊर्जा से 66,780 मेगावाट यानि 16.1 प्रतिशत, डीजल से 589 मेगावाट यानि 0.1 प्रतिशत, हवा से 42,633 मेगावाट यानि 10.2 प्रतिशत, बायो मास पावर/कोजेन से 10,248 मेगावाट, अपशिष्ट से 554 मेगावाट, लघु हाइड्रो से 4944 मेगावाट, नाभिकीय से 6780 मेगावाट बिजली उत्पन्न होती है। देश के सभी धरों तक 24 घण्टे बिजली पहुंचने के लिए मौजूदा क्षमता कम पड़ेगी। इसके लिए वर्तमान क्षमता से कम से कम 30 फीसदी अधिक बिजली की जरूरत होगी। इसके लिये देश में पावर प्लॉटों में 100 फीसदी बिजली उत्पादन करना होगा। बिजली आज पूरी दुनिया की सबसे अहम जरूरत बन गयी है। बिजली के बिना कोई भी देश तरक्की नहीं कर सकता है। थों? से समय के लिये बिजली चली जाने पर हमारे अधिकतर काम रुक जाते हैं। बिजली हमारे जनजीवन का कब मुख्य हिस्सा बन गयी हमें पता ही नहीं चल पाया। आज हमारा पूरा जनजीवन बिजली से जुड़ हुआ है। बिजली का उत्पादन मशीनों से किया जाता है ऐसे में हमें हर हाल में बिजली का दुरुप्योग नहीं करना चाहिये।

सौर ऊर्जा प्रदूषण रहित, निर्बाध गति से मिलने वाला सब सुरक्षित ऊर्जा स्रोत है। भारत में सौर ऊर्जा लगभग बाही महिने उपलब्ध है। सौर ऊर्जा को और अधिक उत्तम करने के लिए हमें अपने संसाधनों का उपयोग करना चाहिए ऊर्जा के मामले में अधिक समय तक दूसरों पर निर्भर न रहा जा सकता है। ऊर्जा के क्षेत्र में हमें अपनी तकनीय और संसाधनों का उपयोग कर आत्मनिर्भारता हासिल करनी ही होगा। यह दुख का विषय है कि बहुत लम्बे समय तक हमने सौर ऊर्जा के उत्पादन व उपयोग पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। हमारे देश की परिस्थितियां विषम होने का अरण हमें सभी उपलब्ध ऊर्जा विकल्पों पर विचार कर होगा। इसके साथ ही ऊर्जा संरक्षण के व्यावहारिक कदमों को अपनाना होगा ताकि बड़े पैमाने पर बिजली की बचत हो सके। हमारे देश में ऊर्जा की मांग तीव्रतांतर से बढ़ रही है। लेकिन उत्पादन में खपत की तुलना में बढ़ोत्तरी नहीं पा रही है। देश में चल रही पुरानी बिजली परियोजनाएँ कभी पूरा उत्पादन नहीं कर पाई हैं। नई स्थापित होने वाली परियोजनाओं के लिए स्थितियां अनुकूल नहीं होती हैं। देश में बिजली के इस संकट को अगर अभी समय रह दूर नहीं किया गया तो आने वाले समय में गंभीर संकट टक्कर सामना करना होगा। दुर्भाग्यवश हमारे देश में खनिजों की पेट्रोलियम, गैस, उत्तम गुणवत्ता के कोयला जैसे प्राकृति संसाधन बहुत समीत मात्रा में ही उपलब्ध हैं। ऊर्जा का

बचत किये बिना हम विकसित राष्ट्र का सपना नहीं देख सकते हैं। आज जिस तर्जी के साथ हम प्राकृतिक और परामर्शिक ऊर्जा के स्रोतों का उपयोग कर रहे हैं। उस रफ्तार से 40 साल बाद हो सकता है हमारे पास तेल और पानी के बड़े भंडार खत्म हो जाए। उस स्थिति में हमें ऊर्जा के गैर-पारापरिक स्रोतों यानि सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा जैसे साधनों पर निर्भर होना पड़ेगा। लेकिन ऊर्जा के गैर-पारापरिक स्रोतों को इस्तेमाल करना थोड़ा मुश्किल है और इस क्षेत्र में कार्य अभी प्रगति पर है। इन स्रोतों को इस्तेमाल में लाने के लिए कई तरह के वैज्ञानिक शोध चल रहे हैं जिनके परिणाम आने और आम जीवन में इस्तेमाल लाने के लायक बनाने में अभी समय लगेगा। इसे देखते हुए अगर हमने अभी से ऊर्जा के स्रोतों का संरक्षण करना शुरू नहीं किया तो आगे चलकर हालात बहुत बदतर हो सकते हैं। केंद्र सरकार का कहना है कि देश के अब सभी 5 लाख 97 हजार 464 गांवों का विद्युतीकरण हो गया है। सरकार की परिभाषा के मुताबिक वे गांव इलेक्ट्रिफाइड माने जाते हैं। जहां बेसिक इलेक्ट्रिकल इंफास्ट्रक्चर हो और गांव के 10 फीसदी मकानों और सार्वजनिक जगहों पर बिजली हो। भारत में बीते एक दशक के दौरान बढ़ती आबादी, आर्थिक सेवाओं तक पहुंच, विद्युतीकरण की दर तेज होने और सकल घरेलू आय में वृद्धि की वजह से ऊर्जा की मांग काफी बढ़ी है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस मांग को सौर ऊर्जा के जरिए आसानी से पूरा किया जा सकता है। सौर ऊर्जा के क्षेत्र में अपर संभावनाओं को देखते हुए अब विदेशी कंपनियों की निगाहें भी भारत पर हैं। आज विश्व का हर देश कागजी स्तर पर तो ऊर्जा संरक्षण की बड़ी-बड़ी बातें करता है। लेकिन ऊर्जा की बर्बादी में सबसे आगे नजर आते हैं। अगर भारत की बात की जाए तो यहां विश्व में पाए जाने वाली ऊर्जा का बहुत कम प्रतिशत हिस्सा पाया जाता है लेकिन इसकी तुलना में हम इसको कहीं ज्यादा खर्चा करते हैं। हमारे देश में आज ऊर्जा बचत के उपायों को शीघ्रतापूर्वक और सख्ती से अमल में लाए जाने की जरूरत है। इसमें देश के हर नागरिक की भागीदारी होनी चाहिए। हर संभव ऊर्जा बचत करें तथा औरें को भी इसका महत्व बताएं।

# ਈਧਨ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੂਰੀ ਕਰੇਗੀ ਪਰਮਾਣੁ ਊਰਜਾ

**भा** रत सरकार के उपक्रम परमाणु ऊर्जा नियम ने मध्यप्रदेश में चार नए परमाणु कार्बोरेंट संयंत्रों की मंजूरी दी है। जल्दी ही दो संयंत्रों की मिल, देवास, सिवनी और शिवपुरी में लगेंगे।

मॉड्यूलर (प्रतिरूपक) रिएक्टर के आधुनिकीकरण के लिए शोध और विकास पर भी धनराशि खर्च की जाएगी। जिससे परमाणु ऊर्जा में नई प्रौद्योगिकी का विकास हो। इसे पीपीपी मॉडल पर क्रियान्वित किया जा रहा है। इसका उद्देश्य देश में स्वच्छ एवं वैकल्पिक बिजली को बढ़ावा देना है। साथ ही प्रधानमंत्री सूर्य धरनि-शुल्क बिजली योजना के तहत छतों पर जो सौर संयंत्र लगाए जा रहे हैं, इन पर भारत सरकार द्वारा दी जाने वाली छूट जारी रहेगी। अभी तक इस योजना के लाभ के लिए 1.28 करोड़ परिवार पंजीयन करा चुके हैं और 14 लाख आवेदन विचाराधीन हैं। इस योजना से 300 यूनिट बिजली मुफ्त मिलेगी। छोटे मॉड्यूलर रिएक्टर (एसएमआर) ऊरत परमाणु संयंत्र माने जाते हैं। इनकी बिजली उत्पादन क्षमता 300 मेगावाट प्रति इकाई है, जो पारंपरिक परमाणु ऊर्जा संयंत्रों की बिजली उत्पादन क्षमता की तुलना में एक तिहाई है। ये संयंत्र न्यूनतम कार्बन बिजली का उत्पादन करते हैं। विकसित भारत के लिए ऊर्जा की उपलब्धता एक बड़ी जरूरत है। इसलिए सरकार सिर्फ पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों पर निर्भर नहीं रहना चाहती है। इसलिए सौर और पवन ऊर्जा पर सरकार पहले ही काफी कुछ कर चुकी है। अतः अब फोकस परमाणु ऊर्जा पर है। क्योंकि इसमें संभवानाएं अधिक हैं। लेकिन परमाणु ऊर्जा उत्पादन में सुरक्षा के सवाल आड़े आते रहे हैं। ऊर्जा सुरक्षा को सरकार सचेत है। ऊर्जा बदलाव के संबंध में एक नीतिगत उपाय किए जा रहे हैं। इनसे तय होगा कि भारतीय अर्थव्यवस्था में किस तरह से पारंपरिक ऊर्जा की जगह धीरे-धीरे अपारंपरिक ऊर्जा के स्रोत का महत्व बढ़ रहा है। इस नीतिगत उपाय के तहत रोजगार, विकास और पर्यावरण से जुड़े मुद्दों का भी समाधान होगा। अतः एवं इसी परिप्रेक्ष्य में निकेल, कोबाल्ट, तांबा और लिथियम जैसी ध्रुतियों के उत्पादों के आयात पर बुल्क क्रमधं परमाणु घटाया जा रहा है। इन उत्पादों का प्रयोग परमाणु और सौर ऊर्जा के साथ दूसरे ऊर्जा उत्पर्जन उपायों में भी होता है। आयात सस्ता होने से इनका निर्माण भारत में करने में आसानी होगी। यही नहीं परमाणु ऊर्जा, नवीनीकरण ऊर्जा और अंतरिक्ष एवं रक्षा क्षेत्रों में इस्तेमाल होने वाली 25 ध्रुतियों पर सीमा शुल्क को पूरी तरह खट्टम कर दिया है। हाल ही के वर्षों में कुछ देशों ने छोटे परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने में सफलता मिली है। इसी का अनुकरण भारत कर रहा है। भारत में एक और असे से एटकी परमाणु बिजली परियोजनाओं में विद्युत का उत्पादन शुरू हो रहा है, वहीं निजी निवेश से परमाणु ऊर्जा बढ़ाने के प्रयास हो रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के सूरत जिले के तापी काकरापार में 22,500 करोड़ रुपए की लागत से बने 700-700 मेगावाट बिजली उत्पादन के दो परमाणु ऊर्जा संयंत्र 22 फरवरी 2024 को राष्ट्र को समर्पित कर दिए हैं। ये देश के पहले स्वदेशी परमाणु ऊर्जा संयंत्र हैं। ये ऊरत सुरक्षा सुविधाओं से युक्त हैं। ये संयंत्र प्रतिवर्ष लगभग 10.4 अरब यूनिट स्वच्छ बिजली का उत्पादन करेंगे। जो गुजरात में बिजली की आपूर्ति के साथ अन्य प्रांतों को भी बिजली देंगे। ये संयंत्र धूत्य कार्बन उत्पर्जन की दिशा में आगे बढ़ने की दृष्टि से मील का पथर साबित होंगे। दूसरी तरफ भारत सरकार ने परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में निजी कंपनियों से 26 अरब डॉलर का निवेश आमंत्रित किया है। यह पहल ऐसे स्रोतों से बिजली बनाने की मात्रा बढ़ाने की दिशा में उत्तरा गया कदम है, जो वायुमंडल में प्रदूषण और तापमान बढ़ाने वाले कार्बनडाल ऑफसाइड का उत्पर्जन नहीं करते हैं। यह पहली बार है जब परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में सरकार निजी कंपनियों से पंजी निवेश की मांग कर रही है। फिलहाल भारत में परमाणु ऊर्जा कुल बिजली उत्पादन की तुलना में महज दो प्रतिष्ठत भी नहीं है। यदि यह निवेश बढ़ाता है तो 2030 तक अपनी स्थापित विद्युत उत्पादन क्षमता का 50 प्रतिशत गैर जीवाश्म ईंधन के उत्योग से प्राप्त लक्ष्य को हासिल करने में सहायता मिलेगी।

# विश्व हिन्दू परिषद् कल, आज और कल

तनवीर जाफरी

**इ** लाहबाद कभी न केवल कांग्रेस बल्कि समाजवादी व आर एस एस व विश्व हिन्दू परिषद् के भी वरिष्ठ व राष्ट्रीय स्तर के नेताओं का गढ़

हुआ करता था। नेहरू-गांधी परिवार की तो यह कर्मसूली थी ही इसके अतिरिक्त पुरणोत्तम दस टंडन, मदन मोहन मालवीय जैसी अनेक विभूतियाँ भी इसी शहर से सम्बद्ध रहीं। इसी तरह दक्षिणपंथी विचारधारा के गांधीय स्वयं सेवक संघ प्रमुख रहे राजेंद्र सिंह उर्फ रज्जु भैया का नाम भी इलाहाबाद से ही जुड़ा हुआ है। ऐसा ही एक नाम था जस्टिस शिव नाथ काटजू का जोकि 1980 के दशक में विहिप के अध्यक्ष भी चुने गये थे। जस्टिस काटजू ने अयोध्या में विवादित बाबरी मस्जिद की जगह पर राम मंदिर के निर्माण के लिए शुरूआती अभियान चलाया था। और इसी दौरान उन्हें नजरबंद भी कर दिया गया था। चूँकि मेरी भी औपचारिक शिक्षा इलाहाबाद में ही हुई इसलिये उस दौर के अनेक विशिष्ट जनों के साथ संबंध रखने का भी सौभाग्य मिला। जस्टिस काटजू भी उन्हीं में एक थे जिनके पास अक्सर मेरा आना जाना रहता था। जस्टिस काटजू विहिप के अध्यक्ष तो जस्तर थे परन्तु वे पूर्णतया धर्मीर्णेश्वर थे। इस्लामी इतिहास का भी उन्हें जबरदस्त ज्ञान था। शिया-सुन्नी विवाद और करबला की घटना जैसे विषयों पर तो वे अक्सर मेरे साथ बातें किया करते और मेरा ज्ञान वर्धन किया करते थे। बात 1977-78 की है उस दौरान मैं इलाहाबाद के मुहल्ले दरियाबाद के इमामबाड़ा सलतवात अली खान नामक एक ट्रस्ट से परिचारिक रूप से जुड़ा हुआ था। यहाँ अनेक धार्मिक आयोजन हुआ करते हैं। इन्हीं में एक चालीसवें का जुलूस (मुर्हरम के चालीस दिन बाद) भी इसी इमामबाड़े से निकला जाता है। इसी जगह से निकलने वाले चालीसवें के जुलूस का प्रारंभिक संबोधन करने के लिये जब मैंने जस्टिस काटजू से निवेदन किया तो वे खुशी खुशी तैयार हो गये। हालांकि उन्होंने अयोध्या में मंदिर के निर्माण के लिए शुरू हुये विहिप आदोलन तथा दरियाबाद की घटी मुस्लिम आबादी को भी रेखांकित किया। परन्तु मेरे संपूर्ण सुरक्षा व शांतिपूर्ण आयोजन के आश्वासन के बाद वे कार्यक्रम में पूर्व स्वयं अपनी एव्वेसडर कार चलाकर बिल्कुल अकेले ही दरियाबाद पधारे। यहाँ दरियाबाद चौराहे पर मौजूद मेरे सम्थियों ने उनका स्वागत किया व पूरे सम्पादन के साथ उन्हें इमामबाड़ा सलतवात अली खान लेकर गये। यहाँ मौजूद समूह के बीच जस्टिस काटजू ने कर्बला की घटना का जिक्र करते हुये न केवल अपनी तरफ से बल्कि विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष होने की हैसियत से विहिप की तरफ से भी हजरत इमाम हुसैन व करबला के शहीदों को बोड़े ही भावपूर्ण शब्दों में ब्रद्दांजलि अर्पित की। शेरबानी, टोपी और चूँचीदार पैजामा जैसा परिधान प्रायः धारण करने वाले काटजू साहब सभी धर्मों का पूरा ज्ञान रखते थे तथा उन्हें सम्पादन भी देते थे। वे विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष होने के बावजूद सभी धर्मों में परस्पर मेल जाल व सद्व्यावक के पक्षधर थे। उन्हें उर्दू आरबी फारसी का भी पूरा ज्ञान था। यह था उस दौर के विश्व हिंदू परिषद का वह चेहरा जिससे भारत का गैर हिन्दू समाज कभी भयभीत नहीं होता था। उसके बाद जबसे गुजरात को गांधीय स्वयं सेवक संघ की प्रयोगशाला कहा जाने लगा तब से इसी विश्व हिंदू परिषद ने खुलकर इस्लाम व अल्पसंख्यकों के प्रति अपनी आक्रामकता दिखानी शुरू कर दी। इसी विश्व हिंदू परिषद में बजरंग दल नामक एक और संगठन तैयार हो गया जो समय समय पर आक्रमक होते नजर आया। आज पूरे देश में विश्व हिंदू परिषद व बजरंग दल पर अनेक आपराधिक मुकदमे चल रहे हैं। इसी विश्व हिंदू परिषद ने योजनाबद्ध तरीके से गुजरात से शुरू कर कॉरेनकाल के दौरान देश के कई राज्यों में मुस्लिम दुकानदारों के प्रति नफरत फैलाकर उनसे सज्जी फल व अन्य सामान खरीदने के लिये हिन्दू समाज के लोगों को मना किया। सीधे शब्दों में मुस्लिमों का व्यवसायिक बहिष्कार करने की कोशिश की गयी। इसी विहिप ने बेटी बच्चाओं बहूलाओं नामक एक अभियान भी चलाया जिसके अंतर्गत किसी हिन्दू लड़की के मुस्लिम लड़के से प्रेम संबंध होने की श्रिति में उस रिश्ते में दखल देना तथा वह अंतर्राष्ट्रीय सम्बन्ध परवान न चढ़ने देना है।







